

ekrRo LokLF; gdnkjH vfHk;ku Iruk
t u l o k n & f j i k V !



राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू इस महत्वकांक्षी मिशन का प्रमुख मकसद प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना था। इस हेतु जननी सुरक्षा योजना एवं जननी एक्सप्रेस आदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है, उपरोक्त मकसद को हासिल करने के लिए रणनीतिक विकल्प के रूप में जोड़े गये। इस मिशन की 8 वर्षीय यात्रा के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं, सेवाप्रदाओं संरचनात्मक व्यवस्थाओं एवं पात्रों तक सुविधाओं की पहुँच के स्तर सतना जिले के रामपुर, नागौद, उचेहरा, मझगवां ब्लाक के कई गांवों के आंगनवाड़ी केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र के सुविधाओं के स्तर को जानने हेतु अहसास संस्था, संतोष देवी मानव विकास संस्था, ग्राम सुधार समिति द्वारा अध्ययन किया गया इस अध्ययन के उभरे तथ्यों को जनसंवाद के लिए दिनांक 11.02.14 को सभी सतना जिले के सामाजिक संस्था और समुदाय के लोग विधायक शंकरलाल तिवारी जी के और सी.एम.एच.ओ. प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह के सामने जनसंवाद में सभी तथ्यों को उठाया गया और समुदाय के तरफ से कई मांगे रखी गई।

48 महिला 55 पुरुषों को मिलाकर 103 लोगों ने जनसंवाद में भाग लिया।

11.02.14, सिद्धांत होटल, सेमरिया चौक, सतना म.प्र.

समुदाय से आई रामरती कोल द्वारा कहा गया कि जब हम प्रसव के लिए अस्पताल गये तो वहाँ हमें जननी एक्सप्रेस लेने या छोड़ने नहीं गई और हमसे नर्स द्वारा पैसा मांगा गया और नर्सों का व्यवहार भी सही नहीं था। इसी तरह उचेहरा से कविता ने कहा कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी नहीं खुलती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव में रहती ही नहीं है उप स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच नहीं होती है। ए.एन.एम. भी कभी नहीं आती, टीकाकरण समय-समय पर नहीं होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से हमारे गांव के लोग वंचित है।

- सभी संस्था के और समुदाय के लोगों की तरफ से अहसास संस्था की सावित्री सिंह ने विधायक शंकर लाल तिवारी को मांग पत्र दिया। और उन्हें याद दिलाया कि चुनाव के पहले आपको यह मांग पत्र दिया गया था, जिसको पूरा करने का आपने वादा किया गया, मांग पत्र में निम्नलिखित मांगे हैं
- सामुदायिक निगरानी प्रक्रिया शासन द्वारा स्थाई रूप से चलायी जानी चाहिए। जिसकी दिशा निर्देश में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को रखा जाए।

- सामुदायिक निगरानी प्रक्रिया को सरकार द्वारा लगातार चलाया जाए।
- प्रत्येक सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक सरकारी अस्पताल में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए।
- प्रत्येक गांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की सूची लगी होनी चाहिए।
- गंभीर संकेत में आने वाली गर्भवती महिलाओं की सूची ग्राम स्वास्थ्य एवं ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों को दी जानी चाहिए।
- गांव स्तर पर भी सामान्य बीमारियों की जानकारी नर्स द्वारा गांव स्तर पर बैठक कर तय की जानी चाहिए एवं इन बीमारियों की दवा आशा एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति के पास भी होना चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान होने वाली विभिन्न जॉचों के लिए माह में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दौरा किया जाना चाहिए।
- जिले स्तर पर जननी एक्सप्रेस/108 एबुलेन्स की संख्याओं को बढ़ाया जाए।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली को लागू किया जा जिसमें स्थानिक स्तर की स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाए।
- गांव स्तर पर होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर मिलने वाले सुविधाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन समिति के लिए स्थानीय स्तर की स्वयंसेवी संस्थाओं की समिति का गठन किया जाए।